

लोक सभा  
अतारंकित प्रश्न सं. 1018  
08 फरवरी, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

एटीयूएफएस

1018. सुश्री एस. जोतिमणि:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) भारत में और विशेष रूप से तमिलनाडु राज्य और करूर निर्वाचन क्षेत्र में टेक्सटाइल इकाइयों की संख्या का ब्यौरा क्या है, जिन्हें संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी और संवितरित की गई राशि का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने कपड़ा और परिधान उद्योग पर जीएसटी के प्रभाव संबंधी कोई अध्ययन किया है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या यह सच है कि जीएसटी लागू होने के बाद ऐसे उत्पादों की कीमतों में वृद्धि हुई है; और
- (घ) यदि हां, तो सरकार ने भारतीय कपड़ा क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में पारदर्शिता लाने और पता लगाने की क्षमता में सुधार के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए हैं?

उत्तर  
वस्त्र राज्य मंत्री  
(श्रीमती दर्शना जरदोश)

(क): भारत, तमिलनाडु और करूर में संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) के तहत सब्सिडी सहायता प्रदान की गई वस्त्र इकाइयों की संख्या नीचे दी गई है:

	मामलों की संख्या	संवितरित की गई सब्सिडी राशि (करोड़ रुपए में)
अखिल भारत	7086	1526.01
तमिलनाडु	656	206.69
करूर	31	10.54

(ख): सरकार ने विशेष रूप से वस्त्र और अपैरल उद्योग पर जीएसटी के प्रभाव संबंधी कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ग): और (घ): तथापि, जीएसटी के कार्यान्वयन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान वस्त्र और अपैरल उत्पादों की कीमतों में उतार-चढ़ाव की सूचना मिली थी, इसने वस्त्र क्षेत्र में विकास को गति दी है।

\*\*\*\*\*